

राजनीतिक व्यवस्था (POLITICAL SYSTEMS)

पाठ-संरचना (Lesson Structure)

- 2.0 उद्देश्य (Objective)
- 2.1 व्यवस्था का अर्थ एवं विशेषताएँ (Meaning and features of System)
- 2.2 राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and definition of Political System)
- 2.3 राजनीतिक व्यवस्था संबंधी आमण्ड के विचार (Almond's views on Political System)
 - 2.3.1 राजनीतिक व्यवस्था के तत्व (Elements of Political System)
 - 2.3.2 राजनीतिक व्यवस्था के आधारभूत लक्षण (Basic features of Political System)
 - 2.3.3 राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएँ (Characteristics of Political System)
- 2.4 राजनीतिक व्यवस्था की सामान्य विशेषताएँ, डाहल के अनुसार (General features of Political System : According to Dahl)
- 2.5 राजनीतिक व्यवस्था उपागम : एक आलोचनात्मक मूल्यांकन (Political System Approach : A Critical Evaluation)
- 2.6 डेविड ईस्टन के व्यवस्था प्रतिरूप की सम्पूर्ण व्याख्या (Complete description of David Easton's System Model)
- 2.7 आमण्ड के व्यवस्था प्रतिरूप की सम्पूर्ण व्याख्या (Complete description of Almond's System Model)
- 2.8 अभ्यास के प्रश्न (Questions for Exercise)
- 2.9 संदर्भ ग्रंथ (Suggested Readings)

2.0 उद्देश्य (Objective)

इस पाठ के अन्तर्गत आप 'व्यवस्था' शब्द का अर्थ समझ सकेंगे, साथ ही व्यवस्था की विशेषताओं से अवगत हो सकेंगे। इसी पाठ में आप राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा एवं विभिन्न चिह्नों द्वारा दी गई परिभाषाओं का विश्लेषण कर पायेंगे। राजनीतिक व्यवस्था संबंधी आमण्ड के विचारों के तहत आप राजनीतिक व्यवस्था के आधारभूत लक्षणों एवं विशेषताओं का अध्ययन कर सकेंगे। राजनीतिक व्यवस्था की सामान्य विशेषताओं के अन्तर्गत राबर्ट डाहल के विचारों से अवगत होंगे। अन्त में, आप राजनीतिक व्यवस्था उपागम का आलोचनात्मक परीक्षण कर सकेंगे।

राजनीतिक व्यवस्था संबंधी डेविड ईस्टन के विचारों का समीक्षात्मक व्याख्या, आलोचनात्मक ढंग से कर सकेंगे।

अन्त में, आमण्ड के व्यवस्था प्रतिरूप का भी समीक्षात्मक व्याख्या कर पायेंगे।

2.1 राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ एवं विशेषताएँ (Meaning and features of Political System)

“वैज्ञानिक राजनीति का विकास तभी किया जा सकता है, यदि राजनीति की सामग्री को, कार्यों की व्यवस्था की तरह समझा जाए। कार्य व्यवस्था चरों का समुच्चय है, जो अपने पर्यावरण से प्रतिनिधित्व, इस ढंग से सम्बद्ध है कि अपेक्षित व्यावहारिक नियमितताएँ चरों के एक दूसरे के प्रति आन्तरिक संबंधों एवं अलग-अलग चरों के समुच्च के बाह्य संबंधों व बाहरी चरों के समुच्चय की विशेषताएँ बताएं।”—मार्टन ए कैपलान।

राजनीतिक व्यवस्था उपागम, जिसे निवेश-निर्गत विश्लेषण के नाम से जाना जाता है, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है : तुलनात्मक राजनीति में, ‘राजनीतिक व्यवस्था उपागम’ ‘राजनीतिक व्यवस्था’ की नई अवधारणा या प्रत्यय पर आधारित दृष्टिकोण है। राज्य के परम्परागत संकल्पना के अन्तर्गत केवल राजनीति के औपचारिक एवं संस्थात्मक ढाँचे पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। राजनीतिक दल, दबाव समूह, कबीले, जाति समुदायों, संगठनों आदि अनौपचारिक, किन्तु महत्वपूर्ण ऐजेंसियों की घोर उपेक्षा पारम्परिक संकल्पना में देखने को मिलते हैं, परन्तु राजनीतिक प्रणाली की संकल्पना राजनीति को एक प्रक्रिया के रूप में समझने का प्रयास है। आज मात्र शासन प्रकार व्यक्तियों के राजनीतिक जीवन को निर्धारित करना ही नहीं, वरन इसके निर्धारण में शासन के अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय कुछ अन्य तत्वों और समुदायों एवं संगठनों के द्वारा भी भाग लिया जाता है और इन सभी को सामूहिक रूप में ‘राजनीतिक व्यवस्था’ कहा जा सकता है।

‘राजनीतिक व्यवस्था’ की अवधारणा का अर्थ समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम सर्वप्रथम ‘व्यवस्था’ शब्द का अर्थ समझ लें, क्योंकि ‘व्यवस्था’ की अवधारणा पर ही ‘राजनीतिक व्यवस्था’ की धारणा आधारित है। व्यवस्था की संकल्पना एक विश्लेषणात्मक संकल्पना है। उल्लेखनीय है कि, ‘व्यवस्था’ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध जीव विज्ञान शास्त्री लुइबिंग बौन बटल नफी ने किया। अर्थात् मूलतः ‘व्यवस्था’ शब्द विज्ञान की शब्दावली है। बाद में विभिन्न समाज विज्ञानों (मार्टन और पारसन्स द्वारा) से गुजरते हुए राजनीति विज्ञान का प्रमुख आधार बन गया।

शाब्दिक परिभाषा के अनुसार, ‘व्यवस्था’ का अर्थ है- “जटिल सम्बन्धित वस्तुओं का समग्र समूह विधि संगठन, पद्धति के निश्चित सिद्धान्त तथा वर्गीकरण का सिद्धान्त।”

अर्थात् एक व्यवस्था संगठित होनी चाहिए अथवा उसमें संगठन हो, उसके अंग संबद्ध हों। व्यवस्था का एक अर्थ “मानवीय संबंधों का स्वरूप भी है। मौटे तौर पर व्यवस्था उन तत्वों के समूह को कहते हैं, जो आपस में एक-दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और एक दूसरे के साथ अन्तःक्रिया करते हैं। यदि व्यवस्था के किसी भाग में गड़बड़ी होती है तो उसका प्रभाव पूरी व्यवस्था पर पड़ता है।”

वस्तुतः व्यवस्था सिद्धान्त विभिन्न अनुशासनों में एकता लानेवाली अवधारणाओं की खोज से संबंधित है। ऐसी ही अवधारणा, जिसके इर्द-गिर्द व्यवस्था सिद्धान्त निर्मित किया गया है।

‘व्यवस्था’ शब्द की परिभाषा विभिन्न प्रकार से की गई है, यथा

बर्टालैन्फी के अनुसार : “व्यवस्था अंतःक्रियाशील तत्वों का समूह है।”

कॉलिन चेरी के शब्दों में : “व्यवस्था एक समग्रता है, जो कई भागों से बनी हुई है। इसे दृष्टिकोण के समग्र प्रभाव के रूप में व्यक्त किया गया है।”

हॉल एवं फ़ैगन के मत में : “व्यवस्था वस्तुओं के परस्पर तथा वस्तुओं और उनके लक्षणों के बीच संबंधों सहित वस्तुओं का समूह है।”

इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि, ‘व्यवस्था’ एक विशिष्ट संरचनात्मक संबंधों और निश्चित प्रक्रियाओं के आधार पर एक-दूसरे के साथ संबद्ध रहती है।

सामान्य अर्थों में, राजनीतिक व्यवस्था का तात्पर्य राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न तत्वों में या भागों में सुव्यवस्था से लिया जाता है। इस सुव्यवस्था से यह अर्थ लिया जाता है कि, राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों में प्रतिमानित संबंधों में एक नियमितता विद्यमान रहती है। राजनीतिक व्यवस्था में कोई स्वतंत्र ईकाई नहीं होती है। समाज व्यवस्था की अनेकों उप-व्यवस्थाओं में एक उप-व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की है, जो अन्य सभी उप-व्यवस्थाओं और आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक से भिन्न प्रकार की ही नहीं, अपितु उन सबसे इस बात में विचित्र है कि, यह सब उप-व्यवस्थाओं और सामाजिक व्यवस्था से पारस्परिकता रखते हुए, अन्तः क्रियाशील रहते हुए भी; बहुत अधिक मात्रा में स्वायत्तता रखती है। यह उन सब व्यवस्थाओं को आदेश ही नहीं देती वरन्, उनको नियंत्रित करने की बाध्यकारी शक्ति भी रखती है। अतः राजनीतिक व्यवस्था समाज की एक उप-व्यवस्था होते हुए भी, एक विलक्षण प्रकार की उप-व्यवस्था है।

2.2 राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and definition of Political System)

परिभाषा : डेविड ईस्टन के अनुसार “राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज के अन्तर्गत उन अंतः क्रियाओं की व्यवस्था को कहते हैं, जिसके माध्यम से अनिवार्य अधिकारिक आवंटन किए जाते हैं, ‘चूँकि समाज में सामाजिक संसाधनों की कमी है। अतः राजनीतिक व्यवस्था का संबंध ‘सामाजिक मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है।”

2.3 राजनीतिक व्यवस्था संबंधी आमण्ड के विचार (Almond's views on Political System)

राजनीतिक व्यवस्था समाज में व्यवस्था बनाए रखने एवं योगों के रूपान्तरण की एक वैद्य व्यवस्था है। यह एक ऐसी बाध्यकारी शक्ति है, जो राजनीतिक व्यवस्था की समस्त गतिविधियों को एक सूत्र में पिरोये रखते हुए, व्यवस्था के रूप में उसे सुसंगठित रूप, विशेष महत्व एवं महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है।”

राबर्ट डहल के अनुसार : “राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का वह स्थायी स्वरूप है, जिसके अन्तर्गत ‘शक्ति’, ‘नियम’ और ‘सत्ता’ महत्वपूर्ण मात्रा में निहित हों।”

पुनः **ईस्टन** का कहना है कि, राजनीतिक व्यवस्था एक खुली एवं सामंजस्यकारी व्यवस्था है, जो एक निश्चित वातावरण में रहती है। यह अपने आप में एक परिपूर्ण सत्ता है, जो वातावरण से प्रभावित तो होती है, किन्तु उसकी दास नहीं होती, अपितु यह पर्यावरण को निर्णायक रूप में प्रभावित करने की क्षमता भी रखती है, ईस्टन ने दो तरह की पर्यावरण की चर्चा की है :-

- (1) अंतः सामाजिक पर्यावरण, जिसके अन्तर्गत पारिस्थितिकी जीवशास्त्रीय, व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवस्था इत्यादि आते हैं तथा
- (2) अतिरिक्त सामाजिक पर्यावरण, जिसमें अन्तर राष्ट्रीय परिघटनाएँ, सामाजिक व्यवस्था का पर्यावरण शामिल होता है। पर्यावरण से ही माँगें उत्पन्न होती हैं।

संक्षेप में, राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था कि एक ऐसी उपव्यवस्था होती है, जिसके विभिन्न भागों में ऐसी संबंध-सूत्रता होती है कि, व्यवस्था के किसी एक भाग में होने वाला कोई परिवर्तन, अन्य अन्तः क्रियाशील अंगों तथा सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में भी अनुकूल परिवर्तन ला देता है।

2.3.1 राजनीतिक व्यवस्था के तत्व (Elements of Political System)

राजनीतिक व्यवस्था के तत्व : आमण्ड के अनुसार, राजनीतिक व्यवस्था के तीन मुख्य तत्व हैं :-

(1) **सर्वव्यापकता या विशुद्धता :** इसका निहितार्थ है कि, राजनीतिक व्यवस्था में भौतिक बल के प्रयोग अथवा उसके भय को प्रभावित करनेवाली सभी परस्पर अन्तःक्रियाएँ आगत व निर्गत सम्मिलित हैं। दूसरे शब्दों में, हम व्यवस्था के अन्तर्गत न केवल उन अंगों को शामिल करते हैं, जो विधि पर आधारित हैं, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका आदि बल्कि, समस्त संरचनाओं को उनके राजनीतिक रूप में शामिल करते हैं, जैसे धर्म, परिवार, जाति आदि।

(2) **अन्योन्याश्रिता :** इसका निहितार्थ है कि व्यवस्था के विभिन्न अंगों में एक प्रकार की संबंध सूत्रता होती है। व्यवस्था के विभिन्न उप-समुच्चय एक-दूसरे से इतनी निकटता के साथ जुड़े हुए हैं कि, एक उप-व्यवस्था समुच्चय में परिवर्तन के कारण दूसरे सभी उप-व्यवस्था समुच्चयों में परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में, व्यवस्था के भागों अथवा उप-व्यवस्था समुच्चयों की सार्थकता सम्पूर्ण व्यवस्था के क्रियान्वयन में ही है। उदाहरण के लिए, संचार व्यवस्था की तकनीक में कोई परिवर्तन राजनीतिक दलों, संवर्गों तथा शासन के विभागों की कार्य शैली में परिवर्तन पर प्रभाव डालता है।

(3) **सीमाएँ :** इसका निहितार्थ है कि, प्रत्येक व्यवस्था किसी एक बिन्दु से प्रारम्भ होती है तथा किसी एक निश्चित स्थान पर उसका अन्त होता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा बिन्दु; जहाँ अन्य व्यवस्थाओं की परिधि समाप्त होती है और राजनीतिक व्यवस्था की परिधि प्रारम्भ होती है, उसे हम “राजनीतिक व्यवस्था की सीमाएँ” कहते हैं।

आमण्ड द्वारा गिनायी गयी इन तीन विशेषताओं के अतिरिक्त, उसकी एक और विशेषता है, जिसके संबंध में उसने अपने सम्पूर्ण विश्लेषण में यह चर्चा की है, कि व्यवस्थाओं की प्रवृत्ति सन्तुलन प्राप्त करने

की ओर होती है। सन्तुलन का अर्थ साधारणतः यह होता है कि कोई भी इकाई दूसरी किसी इकाई के संबंध में अपनी स्थिति बदलेगी नहीं, इसका स्वभावतः ही यह अर्थ होगा कि, विभिन्न इकाइयों ने एक दूसरे के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर लिया है और वे “स्थिरता अथवा समावस्थान की ऐसी स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें वे सामंजस्य, स्थायित्व और सन्तुलन का उपभोग कर रहे हैं।”

2.3.2 राजनीतिक व्यवस्था के आधारभूत लक्षण (Basic features of Political System)

राजनीतिक व्यवस्था एक विचित्र उप-व्यवस्था है, जिसकी विलक्षणता इस बात में है कि यह अन्य उप-व्यवस्थाओं की सीमाओं का आधिकारिक ढंग से निर्धारण कर सकती है तथा साथ ही यह सभी उप-व्यवस्थाओं को आदेश देने की बाध्यकारी शक्ति भी रखती है। इससे स्पष्ट है कि राजनीतिक व्यवस्था के कुछ आधारभूत लक्षण होते हैं, जिनके आधार पर यह अन्य उप-व्यवस्थाओं में से एक होते हुए भी, भिन्न और विलक्षण बन जाती है। आमण्ड एवं पावेल ने इसके कुछ लक्षण इस प्रकार बताए हैं :-

- (क) **भागों या अंगों की पारस्परिक निर्भरता** : अंगों की पारस्परिक निर्भरता का अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्था के सभी अंग या भाग के बीच एक-दूसरे पर निर्भरता की स्थिति रहती है। इसका निहितार्थ है कि जब व्यवस्था में किसी अंग के लक्षणों में परिवर्तन आता है तो इस परिवर्तन के कारण अन्य सभी अंग और स्वयं सम्पूर्ण व्यवस्था प्रभावित होती है।
- (ख) **राजनीतिक व्यवस्था की सीमा** : इसका निहितार्थ है कि एक व्यवस्था कहीं से शुरू होती है और कहीं न कहीं खत्म हो जाती है। अर्थात् राजनीतिक व्यवस्था का एक निश्चित सीमांकन रहता है। इसकी सामान्य व्यवस्था और अन्य उप-व्यवस्थाओं में स्वायत्तता रहती है। यह उसने अन्तः संबंधित होते हुए भी, उनसे स्वायत्त होती है। वस्तुतः राजनीतिक व्यवस्था की सीमा का अर्थ अन्तःक्रियाशील राजनीतिक व्यवस्था के भागों की राजनीतिक भूमिकाओं से लिया जाता है।
- (ग) **राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण** : कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अपने आप में पूर्ण नहीं है। ईस्टन के मतानुसार, राजनीतिक व्यवस्था कई प्रकार के पर्यावरणों से घिरी रहती है और उनके द्वारा प्रस्तुत परिवेश के अन्तर्गत ही सक्रिय रहती है। राजनीतिक व्यवस्था में निवेश पर्यावरण से मिलते हैं और अंत काल में ये निवेश निर्गत के रूप में परिवर्तित होकर पर्यावरण में चले जाते हैं।
- (घ) **वैध भौतिक अवपीड़क या बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग** : राजनीतिक व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं के बीच मूल अंतर यही है कि राजनीतिक व्यवस्था अवपीड़क या ‘बाध्यकारी शक्ति’ पर आवृत्त होती है, जबकि अन्य व्यवस्थाओं के पास औचित्यपूर्ण बाध्यकारी शक्ति नहीं होती है। इस शक्ति के कारण ही राजनीतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं को आदेश देनेवाली तथा उनसे सर्वोपरी बनती है।

मूल्यांकन : राजनीतिक व्यवस्थाओं के उपर्युक्त लक्षणों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि जब हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो इसमें उन सभी अन्तःक्रियाओं को सम्मिलित करते हैं, जो न्याय

संगत भौतिक बाध्यकारिता की शक्ति से संबंधित होती है। इसमें भूमिकाओं का आधार होने के कारण, केवल व्यवस्थापिकाएँ, कार्यपालिकाएँ, न्यायपालिकाएँ और प्रशासकीय अभिकरणों को ही उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता अपितु, उन सब संरचनाओं और प्रक्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है, जिनका राजनीतिक भूमिकाओं से संबंध हो। अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि राजनीतिक व्यवस्था एक विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है, जिसके भागों में अंतःनिर्भरता है, जिसकी सुनिश्चित किन्तु लचीली सीमा होती है, जिसका पर्यावरण होता है और जिसके पास औचित्यपूर्ण बाध्यकारी शक्ति होती है। इन लक्षणों के कारण यह सभी व्यवस्थाओं से अन्तः क्रियाशील रहते हुए भी स्वायत्तता व सर्वोपरिता रखती है।

2.3.3 राजनीतिक व्यवस्था संबंधी 'आमण्ड' के विचार (Almond's views on Political System)

आमण्ड ने राजनीतिक व्यवस्था की पाँच विशेषताएँ बतलायी हैं, जो निम्नवत् हैं :-

(1) **राजनीतिक व्यवस्थाओं की सार्वभौमिकता** : इसका आशय यह है कि आदिम और आधुनिक विकासशील और विकसित सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की राजनीतिक संरचनाएं होती हैं, अर्थात् उनका अन्तःक्रिया संबंधी औचित्यपूर्ण प्रतिमान होता है, जिसके माध्यम से आन्तरिक और बाह्य व्यवस्था बनाई रखी जा सकती है।

(2) **राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता** : सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में समान संरचनाएं होती हैं, जो एक जैसी कार्य करती हैं। यह बात और है कि इनकी आवृत्ति की मात्रा अलग-अलग हो सकती है। मुखरात्मक (Articulative), समूहकारी (Aggregative) और संचारात्मक (Communicative) कार्य; समाज के भीतर विसरित तरीके से अथवा रक्त संबंध या वंश परम्परा की संरचनाओं के माध्यम से सविराम रूप में किए जा सकते हैं।

(3) **राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता** : इसका निहितार्थ है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययनकर्ताओं को उपागम 'संरचना-आवद्ध' (Structure-bound) नहीं होना चाहिए। अर्थात् उसका संबद्ध क्षेत्र राजनीतिक व्यवस्था के विधायी, कार्यपालक और न्यायिक विभागों के सतही अध्ययन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। वरन् उसे उपक्रम, संचार, प्राधिकरण, संशोधन, निषेधाधिकार, प्रतिनिधित्व, वकालत व्याख्या और हितवद्ध समूहों के कारकों की भूमिका को भी 'राज्येत्तर' संस्थाओं के अध्ययन में पूरा-पूरा महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। इन संस्थाओं और एजेंसियों में वे राजनीतिक दल और हितवद्ध समूह शामिल हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था की अवसंरचना कहलाते हैं।

(4) **राजनीतिक संरचना की बहुकार्यकता** : देशकाल के अनुसार, विशेषीकरण की चिन्ता किए बगैर सभी राजनीतिक संरचनाओं बहुकार्यात्मक हैं। परिचय राजनीतिक व्यवस्था के प्रतिमान ने राजनीतिक संरचना की कार्यात्मक विशिष्टता पर बहुत अधिक बल दिया है, जबकि परम्परागत व्यवस्था वालों ने राजनीतिक और सामाजिक संरचना के अविभिन्न और विसरित स्वरूप पर अधिक बल दिया है।

(5) **राजनीतिक व्यवस्थाओं का सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्रित स्वरूप** : सांस्कृतिक अर्थ में, सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं मिश्रित होती हैं, आमतौर पर जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रकारों को आदिम

समझा जाता है वे भी आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की औपचारिक और अनौपचारिक संरचनाएँ होती हैं।

कोई भी व्यवस्था इस अर्थ में आधुनिक या पश्चिमी नहीं होती, जैसे कोई व्यक्ति पूर्णरूप से परिपक्व या अपने बन्धनों व विस्तृत निर्भरता से मुक्त नहीं है।

2.4 राबर्ट डाहल द्वारा दी गई राजनीतिक व्यवस्था की सामान्य विशेषताएँ (General Features of Political System according to Robert Dahl)

राजनीतिक व्यवस्थाएँ अनेक प्रकार के पर्यावरणों से घिरी रहती हैं और इन्हीं के अन्तर्गत सक्रिय होती हैं। अतः इस प्रकार के पर्यावरणी परिवेश में राजनीतिक व्यवस्था के परिचालन से यह व्यवस्था कुछ विशेषताओं से युक्त हो जाती है। डाहल ने इसकी अनेक विशेषताओं का वर्णन किया है और यह माना है कि, ये विशेषताएँ अधिकांशतः राजनीतिक व्यवस्थाओं में सामान्य रूप से पाई जाती हैं। संक्षेप में यह इस प्रकार है :-

(क) राजनीतिक स्रोतों का असमान वितरण : डाहल का मत है कि, “हर राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक विकास के कारण संरचनात्मक विभिन्नीकरण के साथ ही साथ विशेषीकरण आ जाता है। इस विशेषीकरण के कारण राजनीतिक स्रोत धन, शक्ति, सामाजिक स्तर और राजनीतिक कार्य समान रूप से सब व्यक्तियों में विद्यमान नहीं रह सकते। इन स्रोतों पर किसी का अधिक तो किसी का कम नियंत्रण होता है। विशेषीकरण इसके बिना व्यावहारिक नहीं बन सकता। अतः राजनीतिक स्रोत, जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। सबमें समान रूप से बाँट नहीं सकता।

(ख) राजनीतिक प्रभाव की खोज या तलाश : राजनीतिक व्यवस्था में हर व्यक्ति राजनीतिक प्रभाव प्राप्त करना चाहता है, हर व्यक्ति के कुछ उद्देश्य और लक्षण होते हैं। अपने स्वार्थों को वह पूरा करना चाहता है। इनको पूरा करने में राजनीतिक प्रभाव सबसे अधिक सहायक होता है। अतः हर व्यक्ति राजनीतिक शक्ति को किसी न किसी रूप में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रयुक्त करने की कोशिश करता रहता है। शासकीय नीतियों, नियमों और निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता का ही नाम ‘राजनीतिक प्रभाव’ है।

(ग) राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण : राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण होता है। इसका प्रमुख कारण, साधनों का असमान वितरण है। कुछ व्यक्तियों के पास राजनीतिक साधन अधिक होते हैं, जिनके द्वारा वे सरकार को प्रभावित कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों का सरकार पर अधिक प्रभाव होता है, वे अपने इस प्रभाव के द्वारा और अधिक राजनीतिक साधनों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अतः राजनीतिक प्रभाव तक सबकी समान रूप से पहुँच नहीं हो सकती।

(घ) संघर्षपूर्ण उद्देश्यों का समाधान : राजनीतिक व्यवस्था में अनेक हितों और उद्देश्यों वाले व्यक्ति होते हैं। इन हितों और उद्देश्यों में समरूपता या दिशाई एकता हो; यह आवश्यक नहीं। सामान्यतया हितों में संघर्ष ही होता है। समाज ऐसे ही संघर्षपूर्ण हितों का एक ऐसा सामंजस्य रूप है, जिसमें इन सबके होते हुए भी एक स्थिरता रहती है। कई बार यह संघर्षपूर्ण हित, अपनी सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं और समाज कोई समाधान नहीं निकाल पाता। फलतः विभिन्न हितों, स्वार्थों और उद्देश्यों में सन्तुलन बिगड़

कर अस्थायित्व की स्थिति पैदा कर देते हैं। यहां राजनीतिक व्यवस्था अपनी बाध्यकारी शक्तियों का प्रयोग कर हस्तक्षेप द्वारा समाधान निकालता है।

(च) वैधता या औचित्यता का प्रश्न : राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक शक्ति के धारकों (नेताओं) का यह प्रयास रहता है कि, समाज में विद्यमान विभिन्न संघर्षों के समाधान के लिए सरकारी शक्ति का प्रयोग किये जाने पर, उसका आधार यथासम्भव हिंसा, दमन अथवा दण्ड का भय न होकर; यह विश्वास हो कि ये सब जनता के हित के लिए आवश्यक ही नहीं; अनिवार्य हैं। अतः शासकों में, जनता का सहज विश्वास ही राजनीतिक व्यवस्था को औचित्यता प्रदान करता है। अर्थात् प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के नेता अपने कार्यों को वैध बनाने का प्रयास करते हैं।

(छ) एक विचारधारा का विकास : सिद्धान्तों के समूह को 'विचारधारा' कहा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के नेता साधारणतया ऐसे स्थायी और एकीकृत सिद्धान्तों के समूह को अपनाते हैं, जो कि व्यवस्था में उनके नेतृत्व को स्पष्ट और उचित सिद्ध कर सकें। नेता; विचार धारा का विकास इसलिए करते हैं ताकि उनके नेतृत्व को वैधता प्राप्त हो सके अथवा वे अपने प्रभाव को प्राधिकार में परिवर्तित कर सकें। अतः विचारधारा, राजनीतिक व्यवस्था को औचित्य प्रदान करती है।

(ज) अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से अन्तःक्रिया : आज राजनीतिक व्यवस्थाएँ स्वयं में ही न सिमटकर, इसकी राजनीतिक व्यवस्था में भी सम्पर्क स्थापित करने लगी है। ऐसा, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति खासकर संचार साधनों के विकास के कारण हुआ है। आज सम्पूर्ण विश्व एक समाज बन गया है। एक स्थान पर होनेवाली घटना का प्रभाव दूसरे स्थान पर भी पड़ता है। आजकल राजनीतिक व्यवस्थाएँ समाज के पर्यावरण से कहीं अधिक अन्तरराष्ट्रीय पर्यावरण से प्रभावित हैं। इस कारण हर राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं में अन्तःक्रिया बढ़ गई है।

(झ) गत्यात्मकता और तेजस्विता या सजीवता : व्यवस्थाएँ परिवर्तनशील होती हैं और ये प्राणवान भी रहना चाहती हैं। इसका कारण है कि व्यक्तियों की आकांक्षाएँ और आवश्यकताएँ बदलती रहती हैं। इन बदली परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्था का ढलना और अनुरूप होना ही राजनीतिक व्यवस्थाओं को गत्यात्मक या सजीव बनाये रखना है, हर व्यवस्था में परिवर्तन संरचनाएँ समाप्त होती रहती हैं।

इसी तरह पुरानी भूमिकाओं के स्थान पर नई भूमिकाओं का निष्पादन आवश्यक है। राजनीतिक व्यवस्था का बना रहना इस बात पर निर्भर करता है कि वह परिवर्तनों के प्रति कितना सचेत और सजग है। यह सचेतता और सजगता ही राजनीतिक व्यवस्था की गत्यात्मकता और सजीवता है।

उपर्युक्त विशेषताएँ ऐसी सामान्य विशेषताएँ हैं, जो डाहल के अनुसार हर राजनीतिक व्यवस्था में पाई जाती हैं। इनमें मात्रात्मक अन्तर होते हैं, किन्तु प्रकार के अन्तर नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए – ऐसी कोई राजनीतिक व्यवस्था-साम्यवादी व्यवस्थाएँ भी इसमें सम्मिलित हैं – नहीं हो सकती हैं, जिसमें राजनीतिक स्रोतों या प्रभावों का असमान रूप में वितरण नहीं हो। इसी तरह लोकतांत्रिक, स्वेच्छाचारी और सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाओं में सभी के द्वारा वैधता प्राप्त करना अनिवार्य है। अन्यथा इसके प्रभाव में राजनीतिक व्यवस्था टिक नहीं सकेगी। अतः हर राजनीतिक व्यवस्था में उपर्युक्त लक्षण व विशेषताएँ पाई जाती हैं।

2.5 राजनीतिक व्यवस्था उपागम : एक आलोचनात्मक मूल्यांकन (Political System Approach : A Critical Evaluation)

राजनीतिक व्यवस्था उपागम की आलोचनाओं के, सामान्यतया दो आधार प्रमुख कहे जा सकते हैं—

(1) एक तो, विद्वान, 'व्यवस्था' और 'राजनीतिक व्यवस्था' का अभी भी सर्वमान्य अर्थ नहीं कर पाए हैं। इस अर्थ-विभेद और मतभेदों के कारण इस अवधारणा का तुलनात्मक विश्लेषणों में विशेष उपयोग सम्भव नहीं हो पा रहा है।

(2) आलोचना का दूसरा आधार, इस अवधारणा का अत्यधिक परिष्करण है। एक लेखक ने ठीक ही लिखा है कि—“व्यवस्था दृष्टिकोण इतना अधिक सूक्ष्म या नियमनिष्ठ है कि यह करीब-करीब अव्यावहारिक और अनुपयुक्त या अप्रयोज्य बन गया है।” इस कथन में काफी सत्यांश है। स्वयं ईस्टन ने अपनी प्रथम पुस्तक "**The Political System**" में जो अवधारणात्मक विचार रखा था, उसको बाद में प्रकाशित होने वाली दो पुस्तकों में इतना परिमार्जित कर दिया कि, वह परिशुद्धता के उस स्तर तक पहुँच गया जहाँ उसका समझना ही कठिन हो गया। ऐसी अवस्था में उसका आनुभविक उपयोग केवल काल्पनिक ही कहा जा सकता है। आमण्ड एवं पावेल ने इसकी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक व्याख्या करके इसमें और जटिलताएँ उत्पन्न कर दीं।

(3) अन्ततः तुलनात्मक राजनीति में इस अवधारणा को अन्य अवधारणाओं — राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक समाजीकरण के साथ संबंधित करके प्रयुक्त करना आवश्यक हो गया है। अतः राजनीतिक व्यवस्था उपागम की खोज में, वह स्वयं ही इतना जटिल बन गया है कि अनेक विद्वान इसकी उपयोगिता पर ही शंका करने लगे हैं।

विद्वानों ने इसकी कई कमियों (आलोचनाओं) की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, यथा—

- (i) आमण्ड और ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को अत्यधिक स्वायत्तता प्रदान करके इस अवधारणा को आलोचना का शिकार बना दिया है।
- (ii) राजनीतिक व्यवस्था को मूल्य व्यवस्था के साथ इतना जोड़ दिया गया है कि इसकी व्यावहारिक उपयोगिता ही सीमित हो गई है।
- (iii) राजनीतिक व्यवस्था, विश्लेषण की सबसे बड़ी कमजोरी इस बात में है कि यह क्रांतिकारी परिवर्तनों का स्पष्टीकरण देने की बहुत कम क्षमता रखता है।
- (iv) राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा का संबंध केवल राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक व्यवस्था से ही है। इससे तुलनात्मक विश्लेषण आन्तरिक राजनीतिक अध्ययनों तक ही सीमित रह जाते हैं तथा यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से अन्तःक्रिया की अनदेखी करता है, जिससे अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अध्ययन में इस अवधारणा की उपयोगिता नगण्य ही रह जाती है।
- (v) निवेश निर्गत विश्लेषण इतना अधिक सैद्धान्तिक हो गया है कि व्यवहार में यह अप्रयोज्य बन गया है।

समीक्षा—यह सही है कि इसमें अनेक कमियाँ हैं बावजूद, राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा पर आधारित विश्लेषणों ने राजनीतिशास्त्र का एक वैज्ञानिक अध्ययन बनाने में बहुत सहायता की है। इससे एक ऐसा प्रत्यय प्रस्तुत हुआ है, जो पुराने प्रत्ययों के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक अंतरों से अध्ययनों को मुक्त बनाता है और इसी में इसकी अच्छाई या विशेषता निहित है। वस्तुतः राजनीतिक व्यवस्थाओं के माध्यम से नए क्षेत्र का उद्घाटन हुआ है और राजनीति विज्ञानियों को इस प्रकार के अवसर प्रदान किए गए हैं कि वे जो विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, उनका व्यापक राजनीतिक विश्व के साथ संबंध स्थापित किया जाए। मूलतः राजनीतिक व्यवस्था की धारणा संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक के आधार पर व्यवहारपरक संदर्भ में राज्य का अध्ययन करने पर बल देती है।

संक्षेप में, तुलनात्मक राजनीति को परम्परागतता से निकालकर आधुनिक बनाने में “राजनीतिक व्यवस्था” की अवधारणा की आधारभूत देन मानी जाती है।

2.6 डेविड ईस्टन का राजनीतिक व्यवस्था प्रतिरूप (David Easton's Model of Political System)

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद राजनीति के अध्ययन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और राजनीति के अध्ययन के लिए जो नई वैज्ञानिक पद्धतियाँ या उपागम विकसित हुए हैं, उनमें सबसे प्रमुख स्थान व्यवस्था विश्लेषण का है, जो विकसित राजनीतिक जीवन का अध्ययन या राजनीति का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से करता है। तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग करने वाले विद्वानों में ईस्टन का नाम अग्रणी है। वस्तुतः **डेविड ईस्टन** को व्यवस्था-विश्लेषण सिद्धान्त का जनक माना जाता है। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया है। विज्ञान द्वारा स्थापित सिद्धान्त तार्किक प्रामाणिकता से युक्त होते हैं। व्यवस्था विश्लेषण में विश्व एवं इतिहास की समस्त व्यवस्थाएँ समायोजित हो जाती हैं। अतः ईस्टन का व्यवस्था विश्लेषण का सर्वाधिक सिद्धान्त है। ईस्टन का विश्लेषण वास्तविक व्यवस्थाओं का विश्लेषण नहीं, बल्कि समस्त भावी विद्यमान एवं भूत व्यवस्थाओं के सैद्धान्तिक प्रतिरूप का उपकरण मात्र है।

डेविड ईस्टन के ‘व्यवस्था उपागम’ को कई नामों से पुकारा जाता है। इसे व्यवस्था सिद्धान्त, व्यवस्था विश्लेषण, निवेश-निर्गत प्रारूप आदि नामों से पुकारा जाता है।

डेविड ईस्टन का कहना है कि ‘राजनीतिक संगठन’ और ‘संगठित जीवन’ भी एक व्यवस्था का ही प्रकार है। राजनीतिक व्यवस्था को उसने व्यवस्था विश्लेषण की एक मूल इकाई माना है और विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के पारस्परिक व्यवहार को शोध के प्रमुख क्षेत्र के रूप में चुना है। यही कारण है कि डेविड ईस्टन के व्यवस्था उपागम को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है।

डेविड ईस्टन के सिद्धान्त की व्याख्या—डेविड ईस्टन के उपर्युक्त सिद्धान्त की व्याख्या निम्नलिखित ढंग से की जा सकती है—

1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक—“The Political System : An Enquiry into the state of Political Science” में ईस्टन ने स्पष्ट किया कि—राजनीति का सरोकार ‘मूल्यों के आधिकारिक आवंटन’ से है। ईस्टन की इस संकल्पना के अनुसार, ‘प्रणाली’ उन तत्वों के समूह को कहते हैं जो—

- (क) एक-दूसरे से संबद्ध हो,
- (ख) एक-दूसरे पर आश्रित हो, और

(ग) एक-दूसरे पर क्रिया करते हों।

अर्थात्, ईस्टन के ही शब्दों में—“राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अन्दर उन अन्तःक्रियाओं का समूह है, जिसके अन्तर्गत मांगों को निर्गत में बदला जाता है।” राजनीतिक व्यवस्था संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का एक जटिल समूह है; जो समाज के भीतर अनिवार्य या आधिकारिक मूल्यों का विनियोजन करती है।

मतलब यह है कि, इन अन्तःक्रियाओं के माध्यम से ऐसे नियम निर्धारित किए जाते हैं या आदेश दिए जाते हैं, जिनके द्वारा समाज के संसाधनों को भिन्न-भिन्न समूहों के उपयोग के लिए नियत किया जाता है, और इन नियमों तथा आदेशों को समाज के लिए प्रामाणिक या अनिवार्य मानकर इनका पालन किया जाता है।

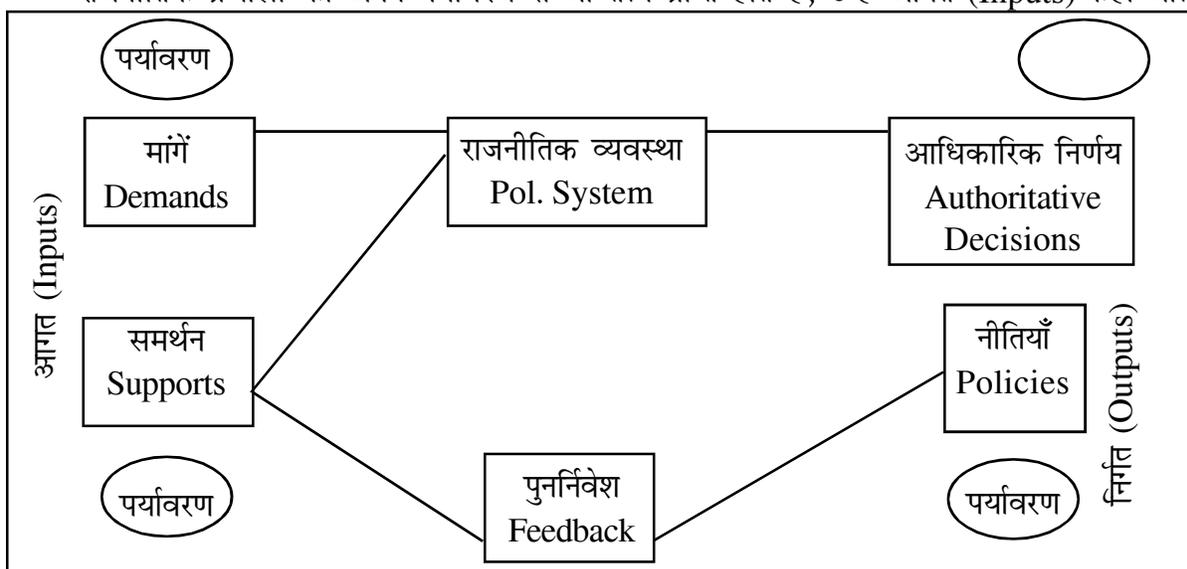
ईस्टन के अनुसार, राजनीतिक प्रक्रिया बंद दायरे के अन्तर्गत नहीं चलती, बल्कि इसके सिरे सामाजिक प्रक्रिया के साथ जुड़े होते हैं। इस दृष्टि से राजनीतिक प्रणाली को **एक खुली प्रणाली मानना चाहिए।** दूसरे शब्दों में, राजनीतिक प्रणाली ‘मूल्यों का आवंटन’ इसलिए करती है, क्योंकि उसे अपने पर्यावरण अर्थात् सामाजिक प्रणाली से मांगें प्राप्त होती हैं। यह आवंटन ‘आधिकारिक’ इसलिए बन जाता है क्योंकि इसे अपने पर्यावरण से ‘समर्थन’ प्राप्त होते हैं। राजनीतिक प्रणाली इन दोनों तत्वों को निर्णयों और नीतियों में रूपान्तरित कर देती है (वस्तुतः नीति स्वयं अनेक निर्णयों का समुच्चय है) ये निर्णय और नीतियाँ, पर्यावरण में वापस चली जाती हैं।

हम यहाँ देखते हैं कि ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को निवेश निर्गत एवं कार्य निष्पादन करने वाली ऐसी व्यवस्था माना है, जो पर्यावरण द्वारा उत्पन्न मांगों का आधिकारिक निर्णय के रूप में रूपान्तरण करती है।

ईस्टन ने इस प्रारूप (प्रतिरूप) को अपनी नई कृति "A Frame work for Political Analysis, 1965" (राजनीतिक विश्लेषण का ढाँचा) में अधिक स्पष्ट रूप से निम्न रेखाचित्र के रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया है—

डेविड ईस्टन के व्यवस्था मॉडल का रेखाचित्र द्वारा विश्लेषण

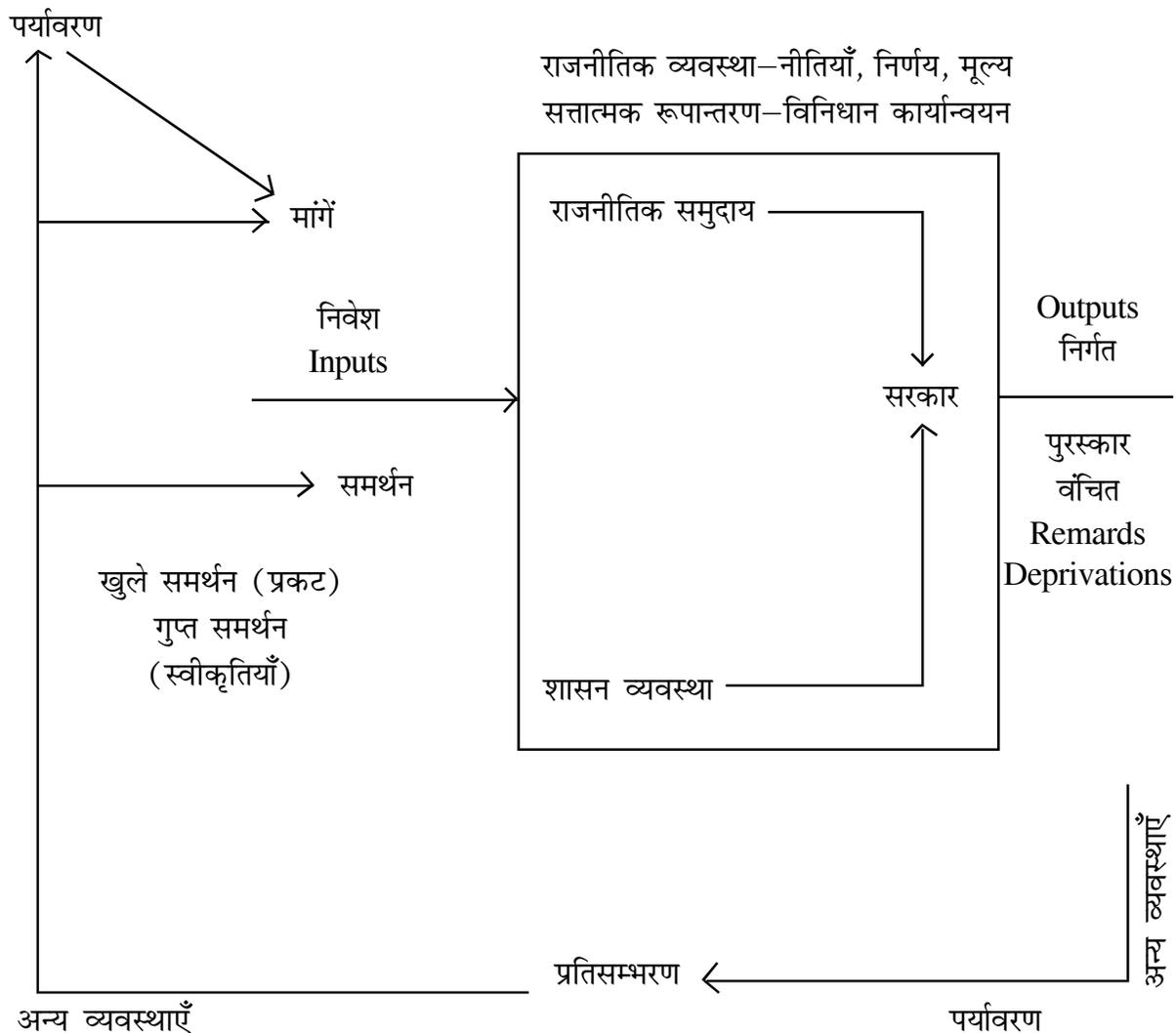
राजनीतिक प्रणाली को अपने पर्यावरण से जो तत्व प्राप्त होते हैं, उन्हें आगत (Inputs) कहा जाता



है और जो प्रणाली का उत्पादन या निर्माण करती है, उन्हें निर्गत (Outputs) कहा जाता है। ईस्टन के अनुसार राजनीतिक प्रणाली को सामाजिक जीवन से 'मांगें और समर्थन' आगत के रूप में प्राप्त होते हैं और यह प्रणाली नीतियाँ और निर्णय बना-बनाकर उन्हें निर्गत के रूप में पर्यावरण की ओर प्रवाहित करती है। यही नीतियाँ और निर्णय आधिकारिक आवंटन का आधार बनते हैं। परन्तु निर्णय भी पर्यावरण में जाकर उसके तत्वों से क्रिया करते हैं जिससे नए आगत अस्तित्व में आते हैं, और ये आगत पुनर्निवेश के माध्यम से राजनीतिक प्रणाली में वापस चले जाते हैं और इस तरह एक जटिल चक्र पूरा होता है। यद्यपि राजनीतिक प्रणाली में बहुत सारी मांगें भेजी जाती हैं, किन्तु उनमें से कुछ रास्ते में ही खो जाती हैं और निर्गत में परिणत नहीं होतीं।

ईस्टन ने माल-निर्माण के रूपक का प्रयोग करते हुए यह संकेत किया है कि मांगें कच्चा माल हैं जिनसे निर्णय रूपी तैयार माल का निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया में लोगों का समर्थन ऊर्जा की भूमिका निभाता है।

डेविड ईस्टन के व्यवस्था मॉडल का रेखाचित्र द्वारा विश्लेषण



ईस्टन द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ईस्टन ने अपनी व्याख्या में निम्न बातों पर अधिक बल दिया है—

- (क) आदान-प्रदान या विनिमय की प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक व्यवस्था में पर्यावरण से व्यवस्था और व्यवस्था से पर्यावरण की तरफ आदान-प्रदान चलता रहता है।
- (ख) राजनीतिक व्यवस्था में उत्पादों या गड़बड़ी की वशीभूतता पर्यावरण के कारण होती है, क्योंकि इस प्रकार के उत्पाद; हमेशा पर्यावरण में ही आते हैं।
- (ग) कार्य सम्पादन की प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक व्यवस्था में कार्य सम्पादन व्यवस्था के अन्दर ही से, एक दिशा से दूसरी दिशा के तरफ चलता रहता है।
- (घ) राजनीतिक व्यवस्था में दबावों और खिंचावों की वशीभूतता, व्यवस्था के अन्दर ही व्यवस्था के आवश्यक परिवर्त्यों के संकटपूर्ण सीमा के आगे ढकेले जाने पर उत्पन्न होती है। अतः यह व्यवस्था के अन्दर होने वाले कारकों से उत्पन्न दबावों की वशीभूतता है तथा इसमें हमेशा प्रतिकूल बनने की ही प्रवृत्ति होती है, किन्तु इसको रोकने के लिए व्यवस्था के अन्दर ही उसके मुआवजे की प्रतिक्रियाओं का होना आवश्यक है, अन्यथा व्यवस्था विखण्डित हो जाती है। प्रायः हर व्यवस्था में ऐसी मुआवजे की प्रतिक्रियाएँ विद्यमान होती हैं।

ईस्टन के व्यवस्था उपागम की विशेषताएँ/लक्षण—ईस्टन ने राजनीति के अध्ययन के लिए इस उपागम को विकसित किया है। जिसकी प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

- (i) राजनीतिक पद्धति; सामाजिक पद्धति का एक अंग है। राजनीतिक पद्धति की तुलना में सामाजिक पद्धति अधिक विस्तारपूर्ण है। सामाजिक पद्धति सम्पूर्ण व्यावहारिकता से ली गई है। राजनीतिक पद्धति द्वारा ही समाज के लिए मूल्यों का निर्धारण किया जा सकता है।
- (ii) राजनीतिक पद्धति में ही अनुक्रियाशीलता और स्वचालित पद्धति प्रस्तुत रहती है, जिसके कारण वह अपनी सीमाओं और संगठन में परिवर्तन करने के लिए समर्थ होती है।
- (iii) राजनीतिक पद्धति में गतिशीलता पाई जाती है, स्थिरता नहीं।
- (iv) राजनीतिक पद्धति एक खुली पद्धति होती है, जिसपर पर्यावरण का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है।
- (v) राजनीतिक पद्धति; आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार के पर्यावरण से घिरी रहती है।
- (vi) **ईस्टन** राजनीति के एकीकृत सिद्धान्त के पक्ष में—यह सिद्धान्त राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्थाओं के व्यवहार की व्याख्या करने और उसकी तुलना करने में सक्षम है।
- (vii) उनका राजनीतिक व्यवस्था में बने रहने या चलते रहने के मामले से सरोकार है।
- (viii) ईस्टन का प्रयोजन; राजनीतिक व्यवस्था का सैद्धान्तिक और प्रायोगिक दोनों परिप्रेक्ष्यों का अध्ययन करना है।

- (ix) ईस्टन का प्रयोजन; राजनीति के अध्ययन को स्वायत्त स्तर तक बनाए रखना है, क्योंकि यह सत्ता के वितरण और इस्तेमाल से प्रभावित मूल्यों के प्राधिकृत विनिधान (Authoritative allocation of values) का अध्ययन है।

इस प्रकार ईस्टन का व्यवस्था उपागम, सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त के निकट है। ईस्टन सार्वजनिक रूप से व्यवस्था उपागम के सकारात्मक पक्ष को मानता है और इसे विशिष्ट समस्याओं अथवा व्यवस्थाओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग में नहीं लाता। उसके लिए व्यवस्था विचारात्मक अथवा अमूर्त धारणा है। वह इस उपागम के द्वारा एक ऐसा ढाँचा प्रस्तुत करता है, जो उसके अनुसार, सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन के लिए एक सामान्य सिद्धान्त के रूप में प्रकट होने की सम्भावनाएँ रखता है।

डेविड-ईस्टन की उपर्युक्त प्रारूप की विस्तार से चर्चा निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत की जा सकती है—

1. निवेश कार्य (Inputs)—ईस्टन के अनुसार, राजनीतिक व्यवस्था के विनेश में मांग एवं समर्थन आते हैं। पर्यावरण समय-समय पर राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष अपनी मांगें रखता है। मांगें तभी प्रभावशाली होती हैं, जब उस पर पर्याप्त समर्थन हो। जब मांगें पर्याप्त समर्थन के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था में निवेशित होती हैं, तो इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। ईस्टन ने चार प्रकार की मांगों और चार प्रकार के समर्थनों का उल्लेख किया है।

चार प्रकार की मांगों में निम्न मांगें आती हैं—

- (i) वस्तुओं और सेवाओं के आवंटन की मांगें,
- (ii) व्यवहार के विनियमन की मांगें, जैसे कि सार्वजनिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, बाजार नियंत्रण आदि।
- (iii) राजनीतिक जीवन में सहभागिता से संबंधित मांगें, और
- (iv) संचार और सूचना से संबंधित मांगें।

चार प्रकार के समर्थनों में निम्न बातें आती हैं—

- (i) माली समर्थन, जैसे कि जनसेवा, कर एवं राजस्व का भुगतान आदि,
- (ii) कायदे कानून का पालन,
- (iii) सहभागितामूलक समर्थन, जैसे कि मतदान व्यवहार, राजनीतिक चर्चा एवं गतिविधियों में भाग लेना आदि।
- (iv) सरकारी सूचनाओं की ओर ध्यान देने की प्रवृत्ति आदि।

2. मांगों का रूपान्तरण—मांगों के रूपान्तरण की प्रक्रिया उन तरीकों को कहते हैं, जिनके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था, अपने समर्थन एवं साधनों के माध्यम से सरकार के निर्णयों या संबद्ध मांगों को स्वीकार-अस्वीकार या उनमें फेर-बदल करने या अन्य उचित कार्यवाही करने के लिए विवश कर सकती हैं। मांगें यह भी समझने में सहायता प्रदान करती हैं कि, पर्यावरण किस तरह राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। मांगों की वैधता, राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता एवं स्थायित्व को समझने में भी

सहायता प्रदान करता है। ईस्टन का अभिमत है कि, शासकों की संबंधित मांगों को भिन्न-भिन्न तरीकों से सम्बोधित किया जा सकता है। उसने इनमें चार कार्यवाहियों (विधियों) को प्रमुख माना है—

- (i) पहली प्रकार की कार्यवाही के अन्तर्गत मांगें स्वीकार कर ली जा सकती हैं या अस्वीकृत कर दी जा सकती हैं।
- (ii) दूसरी, प्रक्रिया के अन्तर्गत वे मांगें जो, किसी सामान्य कार्यवाही में परिवर्तित कर दी जाती हैं।
- (iii) तीसरी, प्रक्रिया के अन्तर्गत कई मांगों को मिलाकर, सबके हित के लिए कोई मांग बना ली जाती है, और
- (iv) चौथी, प्रक्रिया में अनेक मांगों को लोकहित की कसौटी पर जाँच कर कम किया जाता है। मांगों को निर्गत की श्रेणी में आने के लिए अनेक रुकावटों को पार करना पड़ता है।

3. निर्गत कार्य—निर्गत कार्य ऐसे कार्यों को कहा जाता है, जिनमें आधिकारिक निर्णय लिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, जब अपेक्षित समर्थन के आधार पर मांगों को राजनीतिक व्यवस्था में भेजा जाता है, तो उनपर राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत जो निर्णय लिया जाता है या जो नीतियाँ बनायी जाती हैं, उन्हें **निर्गत (output)** कहते हैं।

ईस्टन ने इस संदर्भ में चार प्रकार के निर्गतों की चर्चा की है—

- (i) दोहन—इसके अन्तर्गत लोगों से कर शुल्क तथा व्यक्तिगत सेवा आदि की मांग की जाती है।
- (ii) व्यवहार का विनिमयन,
- (iii) वस्तुओं, सेवाओं, अवसरों, मान-सम्मान इत्यादि का वितरण,
- (iv) प्रतीकात्मक निर्गत (Symbolic outputs), जैसे कि, प्रचलित मूल्यों की पुष्टि, राजनीतिक प्रतीकों का प्रदर्शन, सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों का प्रकाशन आदि।

4. पुनर्निवेश—पुनर्निवेश की प्रक्रिया राजनीतिक प्रणाली को अपने लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता देती है। ईस्टन के अनुसार जब पर्याप्त समर्थन के आधार पर मांगों का निर्गत के रूप में रूपान्तर होता है, तो वे पर्यावरण में जाकर, उसके तत्वों से क्रियाएँ करते हैं। दूसरे शब्दों में, कहें तो पर्यावरण में निर्गत पर अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की जाती हैं, जिससे नये आगत या निवेश का निर्माण होता है और अपेक्षित समर्थन के आधार पर; पुनः मांगों (प्रतिक्रियाओं) को राजनीतिक व्यवस्था में निवेशित किया जाता है। इस प्रक्रिया को पुनर्निवेश (Feedback) प्रक्रिया कहते हैं। इस तरह एक जटिल चक्र पूरा होता है।

5. मांगों का नियमन—उल्लेखनीय है कि, यदि पर्यावरण से बहुत ज्यादा मांगें उत्पन्न होने लगे तो, इससे राजनीतिक व्यवस्था में एक खिंचाव पैदा होगा और राजनीतिक व्यवस्था मांगों के दबाव में असंतुलित होने लगेगी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ईस्टन ने नियामक क्षेत्रों (Regulatory Mechanism) का उल्लेख किया है, जो मांगों को नियंत्रित और अतिभार की रोकथाम करते हैं। ये हैं—

- (i) **दबाव गुट एवं राजनीतिक दल**—ये राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में द्वारपाल की भूमिका अदा करते हैं, जो हर किसी मांग को बेरोक-टोक अन्दर जाने नहीं देते।

- (ii) **सांस्कृतिक क्षेत्र**—इन मांगों पर सांस्कृतिक तन्त्रों का कड़ा अंकुश रहता है, जिसका काम यह जाँच करना है कि; कौन सी मांगें उचित हैं, और कौन-सी अनुचित।
- (iii) **संप्रेषण वाहिकाएँ**—इसके माध्यम से मांगें छनकर; राजनीतिक व्यवस्था के भीतर पहुँचती हैं।
- (iv) **रूपांतरण की प्रक्रिया**—रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान भी मांगों को नियंत्रित किया जाता है। यह कार्य विधायी, कार्यकारी एवं प्रशासकीय निकाय करते हैं।

इस प्रकार, निवेश, निर्गत, पुनर्निवेश एवं मांगों के नियम की प्रक्रियाओं के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था की गतिशीलता बनी रहती है। ईस्टन का कहना है कि, यदि राजनीतिक व्यवस्था को जीवित रखना है, तो यह आवश्यक है कि; इसमें निवेश (आगत) निर्गत की प्रक्रिया निरन्तर होती रहे। यही कारण है कि ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण को, निवेश-निर्गत विश्लेषण भी कहते हैं।

आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Evaluation)—आलोचकों ने ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था उपागम की कतिपय आलोचनाएँ भी की हैं—

प्रथम, आलोचकों का कहना है कि, ईस्टन के व्यवस्था विश्लेषण ने राजनीति को समाजशास्त्र की शाखा बना दिया है, उस पर आश्रित कर दिया है।

दूसरे, ईस्टन ने 'राजनीति' और 'राजनीतिक व्यवस्था' की इतनी व्यापक परिभाषा दी है कि, मूर्त और अमूर्त राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच अन्तर करना कठिन हो गया है।

तीसरे, इस विश्लेषण के द्वारा ईस्टन ने 'संस्थागत दृष्टिकोण' से 'व्यवहारवादी दृष्टिकोण' की ओर जाने का प्रयास किया है, परन्तु वह दोनों के बीच अटक कर रह गया है।

चौथे, आलोचकों के अनुसार, यह उपागम न तो राजनीतिक शक्ति जैसी संकल्पनाओं के विश्लेषण के लिए उपयुक्त है और न ही सामूहिक राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के लिए।

पाँचवें, आनुभविक विधि के उपयोग की दिक्कतों ने भी, 'राजनीतिक व्यवस्था सिद्धान्त' की सीमाओं को उजागर किया है। वस्तुतः राजनीतिक व्यवस्था ऐसी सावयवी वस्तु है, जिसका 'आनुभविक राजनीति' से किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। **मीहान** के अनुसार ईस्टन एक उच्च आनुभविक सम्बद्धता लिए कुछ संकल्पनात्मक संरचना प्रदान करने के अपने वायदे में पूरी तरह असफल रहा है।

छठे, यह उपागम प्रगति का विरोधी एवं यथास्थितिवाद का पोषक है, इतना ही नहीं, यह राजनीतिक व्यवस्था में नित्य होने वाली गड़बड़ियों एवं जोड़-तोड़ पर भी अपना ध्यान आकृष्ट नहीं करता।

सप्तम्, कई विद्वानों के मत में राजनीतिक व्यवस्था को मूल्यों से तथा मानकों से इतना संबद्ध कर दिया गया है कि; उसकी व्यावहारिक उपयोगिता सीमित हो गई है।

अष्टम्, फ्रेज ने इस उपागम को खोखला एवं सारहीन बताया है। उनके मतानुसार, "यह अजीब लगता है कि, एक सिद्धान्त जो तथ्य के प्रति इतना आदरपूर्ण हो, सार की दृष्टि से इतना खोखला हो।"

नवम्, आलोचकों के अनुसार अपने समस्त विश्लेषण में ईस्टन ने, न तो राजनीतिक एवं गैर-राजनीतिक का भेद कर पाया है, और न ही सामाजिक अन्तःक्रियाओं एवं राजनीतिक अन्तःक्रियाओं के अंतर को स्पष्ट कर पाया है।

दशम्, ईस्टन ने अपने विश्लेषण में, अन्तःक्रिया, निवेश-निर्गत, पुनर्निवेश मांगों के नियमन आदि बातों का ऐसा जटिल संकल्पनात्मक ढाँचा प्रस्तुत किया है कि, वह स्वयं इसमें उलझ कर रह गया है। वह न तो मांगों के रूपान्तर की गुत्थियों को सुलझा पाया है, न ही मानवीय समस्याओं को परख सका है। फलतः राजनीति व व्यक्ति दोनों उसकी पकड़ से बाहर हो गये हैं।

ग्यारहवें, इस विश्लेषण की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि, यह क्रान्तिकारी परिवर्तनों की व्याख्या करने या उनका स्पष्टीकरण देने के संबंध में सीमित क्षमता रखता है।

बारहवें, निवेश-निर्गत विश्लेषण इतना अधिक सैद्धांतिक हो गया है कि, व्यवहार में इसकी उपयोगिता कम हो गई है और यह अप्रयोज्य बन गया है।

उपर्युक्त आलोचनाओं एवं सीमाओं के बावजूद भी 'राजनीतिक व्यवस्था' उपागम का महत्व कम नहीं होता। इस उपागम ने तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन एवं विश्लेषण को अधिक ठोस एवं वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया है। तुलनात्मक राजनीति को एक नयी दिशा एवं नया परिप्रेक्ष्य दिया है। राजनीतिक व्यवस्था में निवेश-निर्गत प्रक्रिया की निरन्तरता पर बल देकर तथा उसे पर्यावरण की अन्तःक्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित कर, इस उपागम ने संवर्गों एवं प्रवर्गों का एक ऐसा संकल्पनात्मक ढाँचा प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं का सिंहावलोकन किया जा सकता है।

साथ ही, इसमें संरचनात्मक-कार्यात्मक विश्लेषण की भाँति; व्यापकता होने के बावजूद, इस पर अतिशीलता का आरोप नहीं लगाया जा सकता। इस सिद्धान्त ने पुनर्निवेश जैसी धारणाओं को शामिल कर अपने आपको गतिशील सिद्धान्त के रूप में पेश किया है। इसने किसी खास राजनीतिक व्यवस्था के साथ अपने को आबद्ध करने से बचाकर तुलनात्मक विश्लेषण को नई अन्तर्दृष्टि प्रदान की है।

2.7 आमण्ड द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धान्त अथवा आमण्ड के संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक (कृत्यात्मक) विश्लेषण (Almond's System Model)

राजनीतिक व्यवस्था का संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण, राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र की देन मानी जाती है। संरचनात्मक-कृत्यात्मक विश्लेषण वस्तुतः प्रणाली विश्लेषण का ही विकसित रूप है, जिसे आमण्ड ने ईस्टन के राजनीति व्यवस्था उपागम को अधूरा मानते हुए, इसका विकास किया। इसी विश्लेषण के आधार पर आधुनिक युग में तुलनात्मक राजनीति के रूप में संवारा गया है। व्यवस्था या पद्धति विश्लेषण का एक प्रतिरूप डेविड-ईस्टन द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो दूसरा आमण्ड और पॉवेल द्वारा। ईस्टन द्वारा प्रस्तुत प्रतिरूप को राजनीतिक पद्धति का निवेश-निर्गत कहा जाता है, जबकि आमण्ड और पॉवेल के प्रतिरूप को संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण।

आमण्ड द्वारा स्वीकृत प्रतिरूप, ईस्टन से भिन्न नहीं है। आमण्ड का भी वही उद्देश्य था, जो कि ईस्टन का था-राजनीति के प्रकार्यात्मक सिद्धान्त की खोज। किन्तु आमण्ड ने, ईस्टन के व्यवस्था

विश्लेषण का ही विस्तार संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम के रूप में किया है। साथ ही आमण्ड का विश्लेषण ईस्टन की पद्धति से अधिक प्रतिनिध्यात्मक है। आमण्ड का मुख्य उद्देश्य यह जानकारी प्राप्त करना है कि, राजनीतिक पद्धति अपने परम्परागत ढाँचे से किस प्रकार आधुनिक स्वरूप प्रदान करता है। उसने यह तर्क दिया है कि, निवेश एवं निर्गत तत्व राजनीतिक व्यवस्था के कार्य हैं। आमण्ड ने न सिर्फ इन कार्यों का विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत किया, बल्कि प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त संरचनाओं की भी पहचान की। उसने राजनीतिक व्यवस्था को, मांगों के रूपान्तरण के व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है तथा अपने विश्लेषण में राजनीतिक व्यवस्था की गुत्थियों को खोलने का प्रयास किया है। यही कारण है कि उसका संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण, ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण से अधिक लोकप्रिय हुआ। उल्लेखनीय है कि, आमण्ड ने अपने इस दृष्टिकोण का विकास तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण से किया और तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में इसे ज्यादा उपयुक्त माना। उसने यह दावा किया है कि, इस उपागम के माध्यम से, न सिर्फ सामाजिक पर्यावरण एवं राजनीतिक व्यवहारों के अन्तःसंबंधों का अध्ययन किया जा सकता है, बल्कि स्थानीय एवं प्रांतीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय प्रवृत्तियों तक सुगमता से तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण किया जा सकता है।

आमण्ड की अपनी दृष्टि में “राजनीतिक व्यवस्था सभी स्वतंत्र समाजों में अन्तःक्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जो कम, अधिक, बहुत कुछ वैध भौतिक बाध्यता (शारीरिक बाध्यता) का प्रयोग करने की धमकी देकर एकीकरण या अनुकूलन के कार्यों को सम्पादित करता है।”

(आमण्ड की अपनी पुस्तक "Politics of Developing Areas" में)

आमण्ड की परिभाषा के विश्लेषण से तीन बातें स्पष्ट होती हैं—

- (1) राजनीतिक व्यवस्था एक स्थूल घटक है, जो पर्यावरण को प्रभावित करता है और पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होता है और विधिसम्मत बल प्रयोग का प्रावधान (अन्ततः) उसे बनाये रखने का प्रमुख कारण है।
- (2) अन्तःक्रियाएँ व्यक्तियों के बीच नहीं, किन्तु उनके द्वारा स्वीकृत भूमिकाओं के बीच होती रहती हैं, और
- (3) राजनीतिक व्यवस्था एक खुली हुई व्यवस्था है, जो अपनी सीमाओं के बाहर स्थित घटकों और व्यवस्थाओं के साथ एक अनवरत संचरण के द्वारा जुड़ी हुई हैं।

स्पष्ट है कि आमण्ड और ईस्टन दोनों ही राजनीतिक व्यवस्था को खुली एवं समायोजित तथा आन्तरिक और बाह्य पर्यावरण से घिरी हुई मानते हैं। आमण्ड संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक पक्षों को अलग-अलग करके प्रस्तुत करता है।

आमण्ड के व्यवस्था सिद्धान्त की विशेषताएँ—व्यवस्था के संबंध में आमण्ड की मान्यता क्या है ? “राजनीतिक” से उसका अर्थ समाज में होने वाली कुछ विशेष प्रकार की अन्तःक्रियाओं को इस दृष्टि से अलग करके देखना है कि, दूसरे प्रकार की कुछ विशेष अन्तःक्रियाओं से उनका संबंध स्थापित किया

जा सके तब तो 'व्यवस्था' का अर्थ इन अन्तःक्रियाओं को कुछ विशेष प्रकार के गुणों से विभूषित करना हुआ। आमण्ड ने व्यवस्था की तीन विशेषताएँ बताये हैं—

- (1) व्यापकता,
- (2) अन्तर्निर्भरता, और
- (3) सीमाओं का अस्तित्व।

आमण्ड के व्यवस्था सिद्धान्त के लक्षण अथवा समानताएँ—आमण्ड ने, सभी व्यवस्थाओं में पाँच समानताएँ अथवा लक्षण दर्शायी हैं—

- (1) राजनीतिक व्यवस्थाओं की सार्वभौमिकता,
- (2) राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता,
- (3) राजनीतिक प्रकार्यों की सार्वभौमिकता,
- (4) राजनीतिक संरचनाओं की बहुप्रकार्यता, और
- (5) राजनीतिक व्यवस्थाओं की सांस्कृतिक रूप से मिश्रित विशेषता।

आमण्ड की राजनीतिक व्यवस्था की संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक सिद्धान्त की व्याख्या—ईस्टन के निवेश-निर्गत प्रतिरूप को आमण्ड और पॉवेल ने अपनी संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम के सिलसिले में स्वीकार किया है तथा उसके समान ही तीन धारणाओं का उल्लेख किया है। ये तीन धारणाएँ हैं—

- (1) राजनीतिक व्यवस्था के निवेश।
- (2) रूपांतर प्रक्रिया, और
- (3) राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत।

1. राजनीतिक व्यवस्था के निवेश—आमण्ड ने चार प्रकार के निवेशों की चर्चा की है—

- (i) **राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती**—राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति पहले अपने चारों ओर राजनीतिक प्रणाली के अस्तित्व के प्रति सजग होता है और यह सीखता है कि, अपने हित के लिए इस प्रणाली का सहारा लेना चाहिए। इसके अन्तर्गत व्यक्ति अपने समाज के राजनीतिक जीवन के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण अपनाता है और स्वयं समाज, इसके माध्यम से अपने राजनीतिक मूल्यों, आदर्शों एवं मान्यताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाता है। इस कृत्य या कार्य की प्रमुख संरचनाएँ हैं—परिवार, मित्रमण्डली, शिक्षण संस्थाएँ और बड़े-बड़े समूह। 'भर्ती' वह प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत राजनीतिक समूह, अपने लिए नये सदस्य बनाते हैं अथवा पुराने सदस्यों की जगह; नये सदस्यों को शामिल करते हैं। इस कृत्य से जुड़ी हुई संरचनाओं में उपर्युक्त संरचनाओं के अलावा, वे संगठन भी आते हैं, जिनके लिए

भर्ती की जरूरत होती है।

- (ii) **हित स्पष्टीकरण**—इस प्रक्रिया के अन्तर्गत लोगों के विचारों, अभिवृत्तियों, मान्यताओं और अधिमान्यताओं को राजनीतिक व्यवस्था के प्रति निश्चित मांगों के रूप में परिणत कर दिया जाता है। इसकी इस कार्य को करने वाली मुख्य संरचना 'हित समूह' है, हालाँकि, राजनीतिक दल के कार्यक्रम, चुनाव, अभियान व जन-संचार के साधन भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
- (iii) **हित समूहीकरण**—इस प्रक्रिया के अन्तर्गत विभिन्न समूहों की मांगें एकजुट कर दी जाती हैं, ताकि राजनीतिक सत्ताधारियों का, उन मांगों के प्रति ध्यानाकर्षण हो और वे खुद को दबाव में महसूस करें। इस स्तर पर लोगों की मांगें ऐसे मुद्दों का रूप धारण कर लेती हैं, जिन पर राजनीतिक विचार और कार्यवाही जरूरी हो जाती है। हित समूह की प्रमुख संरचना राजनीतिक दल है।
- (iv) **राजनीतिक संचार**—इस प्रक्रिया के अन्तर्गत विभिन्न समूहों की मांगें, समर्थन और प्रतिक्रियाएँ राजनीतिक व्यवस्था तक पहुँचाए जाते हैं और सरकार द्वारा आवश्यक सूचनाएँ, विवरण और निर्णय जन-साधारण तक पहुँचाए जाते हैं। इस कार्य की प्रमुख संरचनाएँ जनसंचार के साधन हैं। राजनीतिक संचार की प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था के निवेश एवं निर्गत कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का भी कार्य करती है।

2. रूपान्तर प्रक्रिया—तुलनात्मक राजनीति को रूपान्तरण प्रक्रिया के द्वारा; उन्होंने नया सूत्र प्रदान किया है। उसके माध्यम से उन्होंने तुलनात्मक राजनीति को कार्यात्मक दृष्टि दिया है। रूपान्तरण प्रक्रिया दोहरी होती है, जिसमें एक ओर सामान्य क्रियाओं द्वारा मांगों को सत्ता के स्वीकार योग्य बनाया जाता है तो दूसरी ओर, विशिष्ट क्रियाओं द्वारा उसे वास्तव में सत्ता द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। आमण्ड और पॉवेल ने उस आधार पर रूपान्तर प्रक्रिया के निम्नलिखित दो पक्षों का वर्णन किया है—

- (1) राजनीतिक स्तर पर रूपान्तरण प्रक्रिया, और
- (2) शासकीय स्तर पर रूपान्तरण प्रक्रिया।

राजनीतिक स्तर पर रूपान्तरण प्रक्रिया में तीन कार्यात्मक श्रेणियों का उल्लेख किया गया है—

- (क) हित स्वरूपीकरण
- (ख) हित समूहीकरण, और
- (ग) राजनीतिक संचार।

हित स्वरूपीकरण, मांगों के रूपान्तरण का प्रथम चरण है। हित स्वरूपीकरण वह प्रकार्य है, जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं एवं आकांक्षाओं को राजनीतिक व्यवस्था का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से सत्ता को अपने उद्देश्यों के अनुरूप संबोधित करता है।

हित समूहीकरण, रूपान्तरण प्रक्रिया का दूसरा चरण है, जो हितों या मांगों का उनके परीक्षण के बाद संयुक्तीकरण करता है। यह ईस्टन के 'मांगों के न्यूनीकरण' की तरह है। विभिन्न प्रकार की मांगों की जाँचकर उनमें काट-छाँट कर उसका समूहीकरण किया जाता है। यह कार्य राजनीतिक दलों या हित समूहों के द्वारा किया जाता है।

राजनीतिक संचार की प्रक्रिया समाज और अन्य व्यवस्थाओं को एक-दूसरे से जोड़ता है तथा इसी के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था के अन्तःक्रिया सम्भव होता है।

3. राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत-आमण्ड ने तीन प्रकार के निर्गतों का उल्लेख किया है—

- (1) **नियम निर्माण**—नियम-निर्माण का कार्य विधायिका करती है।
- (2) **नियम-अनुप्रयोग**—नियम-प्रयोग का कार्य कार्यपालिका करती है।
- (3) **नियम अधिनिर्णय**—नियम अधिनिर्णय या नियमों की व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका करती है।

इस प्रकार, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन एवं विश्लेषण का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण यह मानकर चलता है कि, राजनीतिक व्यवस्था के उपर्युक्त कार्य सर्वथा आवश्यक है और कोई भी राजनीतिक व्यवस्था, इन कृत्यों को सम्पन्न किए बिना टिक नहीं सकती। वस्तुतः आमण्ड ने संरचनात्मक दृष्टि से, एक विस्तृत राजनीतिक व्यवस्था का प्रारूप/प्रतिरूप निर्मित किया है। किसी भी विकासशील देश की राजनीतिक व्यवस्था को इस प्रतिरूप से मिलाकर वहाँ के राजनीतिक विकास के स्तर को पाया जा सकता है। यही वजह है कि आमण्ड ने अपने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण को “**विकासात्मक-उपागम**” की संज्ञा दी है।

आलोचनात्मक-मूल्यांकन—अन्य उपागमों की तरह संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक की भी कतिपय आलोचनाएँ की गई हैं, यथा—

- (1) ऐसा कहा जाता है कि आमण्ड ने राजनीतिक व्यवस्था को अन्तःक्रियाओं का एक समुच्चय माना है, परन्तु यह स्पष्ट करने का प्रयास नहीं किया कि; व्यवस्था का वास्तविक अर्थ क्या है ? और अन्तःक्रिया से उसका आशय क्या है ?
- (2) आमण्ड का यह दावा कि, उसके संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम के आधार पर सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं के स्वरूप का अध्ययन किया जा सकता है, खोखला एवं अर्थहीन है। चूँकि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाएँ विकासोन्मुख एवं गतिशील हैं, इसलिए प्रकार्यात्मक आधार पर किए गए सामान्यीकरण कई बार भ्रांतिपूर्ण भी सिद्ध हुई है। विकासशील देशों के सिलसिले में इस दृष्टिकोण से यह पता लगाना कठिन हो गया है, कि राजनीतिक व्यवस्था वास्तव में समृद्ध हो रही है; या पतनोन्मुख।
- (3) आलोचकों ने आमण्ड के प्रकार्यवाद को यथास्थितिवाद का पोषक, परिवर्तन का विरोधी एवं पाश्चात्य मूल्यों का समर्थक माना है।

- (4) आमण्ड विशेष प्रकार की संरचनाओं के अन्तर्निर्भरता की प्रकृति को स्पष्ट ढंग से रेखांकित करने में विफल रहे हैं। जैसे-दल पद्धति में हुए परिवर्तन की प्रकृति इत्यादि का अन्वेषण होना चाहिए तथा उसी प्रकाश में राजनीतिक व्यवस्था के निष्पादन में होनेवाली परिवर्तनों का निर्धारण भी किया जाना चाहिए।
- (5) इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत शब्दों को परिचयात्मक ढंग से परिभाषित करना कठिन है तथा यह सुनिश्चित करना भी जटिल है कि, कौन-सी संरचना क्या करेगी।
- (6) इस दृष्टिकोण द्वारा यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि, राजनीतिक व्यवस्था में किस सीमा तक प्रकार्य पूरा हो रहा है या कौन-सा कार्य संचालित नहीं हो रहा है। विश्लेषणात्मक मानदण्ड की बहुत बड़ी कमी इस दृष्टिकोण में देखी जा सकती है।
- (7) संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि, संरचना में होनेवाले परिवर्तन का सम्पूर्ण व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, परन्तु इसके द्वारा परिवर्तनों और उनसे पड़ने वाले प्रभावों की प्रकृति, तीव्रता और मात्रा का ज्ञान प्राप्त करने का कोई सुलभ साधन उपलब्ध नहीं हो पाया है।
- (8) **आमण्ड** राजनीतिक व्यवस्था की स्वायत्तता पर आवश्यक रूप से बल देता है, जबकि आधुनिक युग में राजनीतिक संस्थाएँ, दूसरे समृद्ध और विकसित व्यवस्थाओं से प्रभावित होती हैं।

निष्कर्ष—उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से यह कहा जा सकता है कि, उपर्युक्त आलोचनाएँ एक सीमा तक यथार्थ का बोध कराती हैं। वस्तुतः आमण्ड स्पष्ट मान्यताओं और तथ्यों में उलझा नहीं रहना चाहता, बल्कि उसकी गहराई तक खोज करने में दिलचस्पी रखता है, जो उन्होंने उपर्युक्त आक्षेपों को पहले विचारवद्ध की परिधि से बाहर रहने की बात बताई है।

इन सीमाओं के बावजूद तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के क्षेत्र में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज तुलनात्मक शासन और राजनीति के अध्ययन में संरचनात्मक कृत्यात्मक पद्धति विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुई है, क्योंकि इससे उन राजनीतिक प्रणालियों की तुलना के लिए मानक आधार मिल जाते हैं, जो अन्यथा एक दूसरे से बहुत भिन्न हो। इसने तुलनात्मक राजनीति के अध्येताओं एवं अनुसंधानकर्ताओं के लिए सर्वथा एक नया परिप्रेक्ष्य प्रदान किया है। इस दृष्टिकोण में ऐसे प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है, जो परिभाषा की दृष्टि से कठिनाई अवश्य उत्पन्न करते हैं; किन्तु विश्लेषण और आनुभविक दृष्टि से परिमाणनीय है। अर्थात् तुलनात्मक राजनीति को परम्परागत जकड़नों से मुक्त कर एक नवीन व गत्यात्मक अनुशासन बनाने का सूत्रपात संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य द्वारा ही हुआ है।

राजनीतिक प्रणाली के संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक प्रतिरूप का विस्तृत निरूपण **ग्रेब्रियल ए आल्मंड** और **जी. बी. पॉवेल** की चर्चित कृति “Comparative Politics : A developmental Approach” (तुलनात्मक राजनीति : विकासात्मक उपागम) 1966 के अन्तर्गत किया गया है। इस प्रतिरूप को रेखाचित्र के रूप में इस तरह व्यक्त कर सकते हैं :-

	पर्यावरण (Environment)			पर्यावरण (Environment)		
	कृत्य (Function)	संरचना (Structure)		कृत्य (Function)	संरचना (Structure)	
I N P U T S आगत	1. राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती (Political socialization and recruitment)	परिवार, मित्रमण्डली शैक्षिक और धार्मिक संगठन इत्यादि (Family, peer group, school, church etc.)	राजनीतिक प्रणाली (Political System)	4. राजनीतिक संप्रेषण (Political Communication)	जन संचार के साधन (Mass Media)	O U T P U T S निर्गत
	2. हित स्पष्टकीरण (Interest Articulation)	हित समूह (Interest Groups)		5. नियम-निर्माण (Rule-making)	विधायिका (Legislature)	
	3. हित समूहन (Interest Aggregation)	राजनीतिक दल (Political Parties)		6. नियम अनुप्रयोग (Rule-Application)	कार्यपालिका (Executive)	
			7. नियम-अधिनिर्णयन (Rule-Adjudication)	न्यायपालिका (Judiciary)		

आमण्ड एवं पॉवेल के व्यवस्था मॉलड (संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक) का रेखाचित्र द्वारा विश्लेषण

2.8 अभ्यास के प्रश्न (Questions for Exercise)

1. राजनीतिक व्यवस्था के अर्थ एवं परिभाषा दें तथा इसकी विशेषताओं की समीक्षा करें।
(Discuss the meaning and definition of Political System and discuss features.)
2. राजनीतिक व्यवस्था के आधारभूत लक्षण क्या हैं ? स्पष्ट करें।
(What are the basic features of Political System ? Explain.)
3. राजनीतिक व्यवस्था के आधारभूत तत्वों की समीक्षा करें।
(Discuss the basic elements of Political System.)
4. डेविड ईस्टन के व्यवस्था प्रतिरूप का आलोचनात्मक परीक्षण करें।
(Critically examine David Easton's System Model.)
5. ऑमण्ड के व्यवस्था प्रतिरूप का समीक्षात्मक परीक्षण करें।
(Critically examine Almond's System Model.)

2.9 संदर्भ ग्रंथ (Suggested Readings)

- | | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| (1) तुलनात्मक राजनीति | — | एस० आर० महेश्वरी |
| (2) तुलनात्मक शासन एवं राजनीति | — | गाँधी जी राय |
| (3) तुलनात्मक राजनीति | — | जे० सी० जौहरी |
| (4) तुलनात्मक राजनीति | — | ओ० पी० गावा |
| (5) तुलनात्मक राजनीति | — | सी० बी० गेना |
| (6) तुलनात्मक राजनीति | — | जैन एवं फाड़िया। |

